

Army finalises purchase of arms worth Rs 40,000 cr to replace ageing weapons

The Army needs around 7 lakh 7.62x51 mm assault guns to replace its INSAS rifles.

New Delhi: The Army has finalised one of its biggest procurement plans for infantry modernisation under which a large number of light machine guns, battle carbines and assault rifles are being purchased at a cost of nearly Rs 40,000 crore to replace its ageing and obsolete weapons.

The broad process to acquire around 7 lakh rifles, 44,000 light machine guns (LMGs) and nearly 44,600 carbines has been finalised and the defence ministry is on the same page with the Army in moving ahead with the procurement, official sources said.

The world's second largest standing Army has been pressing for fast-tracking the procurement of various weapons systems considering the evolving security threats including along India's borders with Pakistan and China.

Apart from kick-starting the procurement process, the government has also sent a message to the Defence Research and Development Organisation (DRDO) to expedite its work on various small arms, particularly on an LMG.

The sources said a fresh RFI (request for information) to procure the LMGs will be issued in the next few days, months after the defence ministry scrapped the tender for the 7.62 calibre guns as there was only one vendor left after a series of field trials. The plan is to initially procure around 10,000 LMGs.

The Army has also finalised the specifications for a new 7.62 mm assault rifle and the Defence Acquisition Council (DAC), the defence ministry's highest decision making body on procurement, is expected to give the go-ahead for the much needed procurement soon.

"The General Service Quality Requirements (GSQR) for the new assault rifle has been finalised. The procurement plan will soon be placed before the DAC for approval," said a senior official, who is part of the acquisition process.

In June, the Army had rejected an assault rifle built by the state-run Rifle Factory, Ishapore, after the guns miserably failed the firing tests.

The procurement of assault rifles has witnessed significant delays due to a variety of reasons including the Army's failure to finalise the specifications for it.

The Army needs around 7 lakh 7.62x51 mm assault guns to replace its INSAS rifles.

The Army had issued RFI for the rifles in September last year and around 20 firms responded to it. An RFI is a process whose purpose is to collect information about capabilities of various vendors.

In June, the Army had kick-started the initial process to procure around 44,600 carbines, nearly eight months after a tender for it was retracted, also due to single-vendor situation. Around half a dozen firms including a few global arms manufacturers have responded to the RFI.

Army sources said various specifications for the LMGs and battle carbines were tweaked to ensure that the problem of single vendor does not recur.

The combined cost of the LMGs, assault rifles and carbines will be in excess of Rs 40,000 crore, said an official.

On DRDO missing a number of deadlines in finalising the LMG, an official said the defence secretary has called a meeting this week of all stakeholders to discuss the project.

"The infantry modernisation plan is a major initiative of the Army and it will significantly bolster the overall capability of the foot soldiers," said a senior army official.

The issue was extensively discussed at the recently concluded Army Commanders conference which felt modernisation of the Army must be in tune with the evolving security threat facing the country.

Defence Minister Nirmala Sitharaman conveyed to the Army during the conference that modernisation of the force was a priority for the government and all its "deficiencies" will be addressed to strengthen its combat capability.



Mon, 30 Oct, 2017

थल सेना के लिए खरीदे जाएंगे 40 हजार करोड़ के हथियार

भारतीय थल सेना ने इन्फैंट्री के आधुनिकीकरण के लिए सबसे बड़ी खरीद योजनाओं में से एक को अंतिम रूप दे दिया है।

भारतीय थल सेना ने इन्फैंट्री के आधुनिकीकरण के लिए सबसे बड़ी खरीद योजनाओं में से एक को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी संख्या में हल्की मशीनगन, कार्बाइन और असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। नए हथियार पुराने और चलन से बाहर हो चुके हथियारों की जगह लेंगे। करीब सात लाख राइफल, 44 हजार लाइट मशीन गन (एलएमजी) और करीब 44,600 कार्बाइन की खरीद की विस्तृत प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना पर लंबे समय से इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देने का दबाव था। चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यह चिंता और बढ़ गई थी। विदेश से हथियारों की खरीद के साथ ही रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को भी अपने स्तर पर लाइट मशीनगन जैसे छोटे हथियार तैयार करने को कहा है। अगले कुछ ही दिनों में एलएमजी की खरीद के लिए 'जानकारी का अनुरोध' (रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आरएफआइ) जारी की जाएगी। कुछ महीने पहले ही रक्षा मंत्रालय ने 7.62 कैलिबर बाकी पेज 8 पर गन्स के लिए फील्ड ट्रायल के बाद मैदान में एक ही कंपनी के बचे रहने के कारण प्रस्ताव रद्द कर दिया था।

खरीद प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 'नई असॉल्ट राइफल के लिए 'जनरल सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स' (जीएसक्यूआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है। खरीदारी योजना को मंजूरी के लिए जल्द ही डीएसी के पास भेजा जाएगा।' बताते चलें कि ईशापुर की सरकारी राइफल फैक्टरी में निर्मित असॉल्ट राइफल को जून में सेना ने अस्वीकार कर दिया था। ये हथियार परीक्षण में नाकाम साबित रहे थे।

असॉल्ट राइफलों की खरीदारी में विभिन्न कारणों से देरी हुई जिसमें इसकी विशेषताओं को अंतिम रूप देने में सेना की नाकामी भी शामिल है। जून माह में सेना ने करीब 44,600 कार्बाइन की खरीदारी की शुरुआती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इकलौते विक्रेता के बचे रह जाने पर निविदा रद्द कर दी गई थी। इस आरएफआइ पर कुछ वैश्विक हथियार निर्माताओं समेत करीब आधा दर्जन फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई थी।

सेना के लिए 40 हजार करोड़ के नए हथियार

■ पीटीआई, नई दिल्ली

पाकिस्तान और चीन सीमा पर खतरों के मद्देनजर सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए हथियारों की खरीद की बड़ी योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें करीब 40,000 करोड़ रुपये लागत से हल्की मशीन गन, कार्बाइन और असॉल्ट राइफलों खरीदी जाएंगी। नए हथियार पुराने और चलन से बाहर हो चुके हथियारों की जगह लेंगे। इसे अब तक की सबसे बड़ी खरीद योजनाओं में से एक माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, करीब 7 लाख राइफल, करीब 44,000 लाइट मशीन गन (LMG) और 44,600 के करीब कार्बाइन खरीदने की योजना है। कुछ दिनों में एलएमजी की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की जाएगी। कुछ महीने पहले रक्षा मंत्रालय ने 7.62 कैलिबर गंस का टेंडर रद्द किया था क्योंकि कई फील्ड ट्रायल के बाद इसका इकलौता विक्रेता ही बचा था। अब शुरुआत में 10,000 एलएमजी खरीदने का प्रस्ताव है। रक्षा मंत्रालय की हथियार खरीद से जुड़ी सबसे बड़ी निर्णायक संस्था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जल्द ही खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि सीमा पार की चुनौतियों से निबटने के लिए सेना काफी समय से आधुनिक हथियारों की योजना को मंजूरी देने की मांग कर रही है।

खरीद योजना को मंजूरी मिली

7 लाख के करीब राइफलों खरीदी जाएंगी सौदे में।

10,000 एलएमजी खरीद का शुरुआती प्रस्ताव।

44,000 लाइट मशीन गन (LMG) खरीदने की तैयारी।

44,600 के करीब कार्बाइन खरीद की भी योजना।



NBT नजरिया

भारतीय सेना दुनिया की ताकतवर फौजों में से एक है, लेकिन एक सच यह है कि अभी जंग होने की स्थिति में हमारी सेना को भारी मुश्किल हो सकती है। वजह है आधुनिक हथियारों की भारी कमी। ऐसे में बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी अच्छी खबर है। लेकिन यह साजोसामान विदेशी सप्लायरों से ही मिलते रहे और हम सबसे बड़े हथियार आयातक बने रहे, तो कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। देश के रोजगार से लेकर सामाजिक विकास तक बड़ी तब्दीली के लिए जरूरी है कि घरेलू कंपनियों को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उतारा जाए।

INSAS राइफलों की जगह नई गन

सेना के आधुनिकीकरण की इस योजना से पैदल सैनिकों की क्षमता में जबर्दस्त इजाफा होने की उम्मीद है। सेना की मौजूदा INSAS राइफलों की जगह लेने के लिए 7 लाख 7.62x51 मिमी असॉल्ट गंस की जरूरत है। हाल में आर्मी कमांडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि सेना का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है।

LMG पर DRDO करेगा तेजी से काम

हथियारों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सरकार ने DRDO से कहा है कि वह छोटे हथियारों खासकर हल्की मशीन गन पर काम तेज करे। डीआरडीओ एलएमजी फाइनल करने की आखिरी तारीख कई वार मिस कर चुका है। पूरे प्रॉजेक्ट पर चर्चा के लिए रक्षा सचिव ने इसी हफ्ते मीटिंग बुलाई है।

दैनिक जागरण

सेना खरीदेगी 40 हजार करोड़ के हल्के हथियार

नई दिल्ली, प्रेटर : भारतीय थलसेना ने पैदल सेना के आधुनिकीकरण की कवायद के चलते बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी कर ली है। तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपये की हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और राइफलों की खरीद की जाने वाली है।

सूत्र के अनुसार देश की पैदल सेना पाकिस्तान व चीन से लगी सीमाओं

पर बढ़ते खतरे को देखते हुए लंबे समय से विभिन्न हथियार प्रणालियों की मांग करती आ रही है। लिहाजा, व्यापक प्रक्रिया के तहत सात लाख राइफलों, 44 हजार लाइट मशीन गन (एलएमजी) व 44,600 कार्बाइन खरीदने का फैसला ले लिया गया है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय और सेना एकमत है। 7.62 गुणे 51 मिमी सात लाख राइफलों आइएनएसएस राइफलों की

जगह लेंगी। जून में ही सेना ने 44,600 कार्बाइन हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसका टेंडर निकालने के 8 महीने बाद छह कंपनियों आरएफएल के लिए कतारबद्ध हैं। खरीद प्रक्रिया को शुरू करने को सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को संदेश दिया है कि वह विभिन्न छोटे हथियारों पर विशेषज्ञता के काम करे। यह इसलिए भी बेहद जरूरी हो गया है कि रक्षा मंत्रालय

की ओर से 7.62 कैलिबर गनों का टेंडर भी रद्द किया जा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि फील्ड ट्रायल में वह विफल रहीं और यह सभी एक ही वेंडर से आती थीं। सरकार की योजना है कि शुरुआत में 10 हजार हल्की मशीन गन हासिल की जाएं।